[2022] 15 एससीआर. 287

मेखा राम और अन्य इत्यादि, इत्यादि

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य इत्यादि, इत्यादि

(सिविल अपील सं. 2229-2234 / 2022)

29 मार्च, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरथ्ना, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून:

राजस्थान चिकित्सीय और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 - पुनर्स्थापन - अपीलकर्ता, जो सहायक नर्सिंग और प्रसूति विज्ञान या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता, लेखा लिपिक और अन्य समान रूप से स्थित पदों पर काम कर रहे थे, उन्होंने तीन वर्षीय अवधि के सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया - आवेदन की प्रस्तुति सेवारत प्रत्याशियों के रूप में और अध्ययन अवकाश के लिए भी आवेदन किया - अपीलार्थियों द्वारा यचिकाएँ जिसमें प्रार्थना की गई कि संबंधित प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा उन्हें दिए गए अध्ययन अवकाश को प्रतिनियुक्ति पर तय किया जाए - एकल न्यायाधीश ने याचिकाएं मंजूर कीं-प्रभागीय पीठ ने तय किया कि सेवानिवृत्त प्रत्याशियों द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर बिताया गया समय प्रतिनिधित्व पर समय के रूप में नहीं माना जाएगा और केवल अवकाश के रूप में माना जाएगा जो प्रत्याशियों के हक में हो। - पेंडेंसी के दौरान, एकल न्यायाधीश द्वारा पास की गई निर्णय और आदेश की अवमानना के ख़तरे में, अपीलार्थियों को राशि भुगतान की गई थी - प्रभागीय पीठ ने निर्देशित किया कि राज्य को अपीलार्थियों को उनके प्रशिक्षण की अवधि के रूप में छुट्टी के रूप में भुगतान की गई अधिक राशि को आसान समान किस्तों में वसूलने का अधिकार होगा - अपील पर, निर्धारित किया गया: अपीलार्थियों को अधिक भुगतान की गई राशि राज्य प्राधिकरण की किसी भूल के कारण नहीं थी - अधिक राशि एकल न्यायाधीश द्वारा पास किए गए आदेश के अनुसार भुगतान की गई थी-किसी को भी अदालत द्वारा पास किए गए गलत आदेश का लाभ उठाने की अनुमति नहीं हो सकती जो बाद में उच्च फोरम/ अदालत द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है - अदालत के आदेश के कारण कोई पक्ष प्रतिकूलित नहीं होना चाहिए - एकल न्यायाधीश द्वारा पास किया गया आदेश

उच्च न्यायालय की प्रभागीय पीठद्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है और इस प्रकार, धारा 144 CPC को भी लागू करते हुए, प्रभागीय पीठ द्वारा अस्वीकृत एकल न्यायाधीश द्वारा पास किए गए आदेश के अनुसार भुगतान की गई राशि याचिका कर्ताओं द्वारा वापिस की जानी चाहिए - इस प्रकार, उच्च न्यायालय की प्रभागीय पीठराज्य के पक्ष में राशि वापिस लेने के लिए स्वतंत्रता रखने में उचित थी जो याचिका कर्ताओं को अधिक भुगतान की गई थी - सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियम, 1990 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 144।

पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह **(2015) 4 एस सी सी 334: [2014] 13 SCR 1343** *- नालागू माना गया। इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल* **(2020) 8 एस सी सी 129 : [2020] 3 SCR 1***; साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य* **(2003) 8 एस सी सी 648 : [2003] 4 Suppl. SCR 651**; *उसेफ मथई बनाम एम. अब्दुल खदिर* **(2002) 1 एस सी सी 319 : [2001] 5 Suppl. SCR 118 - संदर्भित किया गया।**

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2014] 13 SCR 1343	**नालागू माना गया**	**पैरा 4**
[2020] 3 SCR 1	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 5.1**
[2003] 4 Suppl. SCR 651	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 5.1**
[2001] 5 Suppl. SCR 118	**संदर्भित किया गया**	**पैरा 6.2**

सिविल अपील अधिकारिकता: सिविल अपील संख्या 2229-2234 का 2022

राजस्थान के न्यायाधीश की उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के 06.05.2016 के निर्णय और आदेश से, डी.बी. विशेष अपील (याचिका) संख्या 1883, 1887, 1990 का 2014 में, डी.बी. विशेष अपील (याचिका) संख्या 289 का 2015 में, डी.बी. विशेष अपील (याचिका) संख्या 1888 का 2014 में और डी.बी. विशेष अपील (याचिका) संख्या 191 का 2015 में।

साथ में

सिविल अपील संख्या 2235-2249, 2250-2251, 2252, 2253-2256 / 2022

आर.के. सिंह, श्रीमती नीरज सिंह, कुमार गौरव, श्रीमती रितु रेनीवाल, प्रवीण पाठक, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अंकुर रास्तोगी, श्रीमती प्रिया रास्तोगी, श्रीमती लक्ष्मी अरविंद, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए।

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्पित पारकाश, मिलिंद कुमार, श्रीमती रुचि कोहली, रोहित के. सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादियो

न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया गया।

एम. आर. शाह, न्यामूर्ति

1. आपत्तिजनक सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 06.05.2016 के साथ संतुष्ट और आहत महसूस करते हुए, जो राजस्थान, जयपुर पीठ जयपुर के उच्च न्यायालय के विभाजन पीठ द्वारा D.B.स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1883/2014 और अन्य जुड़े हुए अपीलों में पास किया गया था, जिससे उच्च न्यायालय के विभाजन पीठ ने कहे गए अपीलों को मंजूरी दी है और उच्च न्यायालय के सिख्षित एकल न्यायाधीश द्वारा पास किए गए प्रत्येक न्यायादीशों और आदेशों को रद्द कर दिया है और तय किया है कि सेवा में उम्मीदवारों द्वारा तीन वर्षीय नर्सिंग प्रशिक्षण को प्रतिनियुक्ति की अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता और केवल उम्मीदवारों के लिए जो कुछ भी देय हो वह छुट्टी के रूप में ही माना जाएगा और नतीजतन राज्य के पक्ष में अधिक राशि को वापस प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता आरक्षित की है, जो प्रशिक्षण की अवधि को उसके लिए स्वीकार्य छुट्टी की अवधि के रूप में मानते हुए मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं को भुगतान की गई थी, मौलिक रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपीलें की हैं।

2. मूल याचिका पत्रकार्ता सहायक नर्सिंग और प्रसूति विज्ञान या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता, लेखा लिपिक और अन्य समान रूप से स्थित पदों पर काम *कर रहे* हैं। वे राजस्थान चिकित्सीय और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम,1965 के सदस्य हैं। उन्होंने तीन वर्षीय अवधि के जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया था जिसे सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियम, 1990 ('रूल्स 1990' के रूप में संदर्भित) के अनुसार विनियमित किया गया था।

2.1 सभी मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने इन-सर्विस उम्मीदवारों के रूप में आवेदन, परिस्कृत प्रोफार्मा में प्रस्तुत किए, सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। रूल्स 1990 के नियम 9 के तहत सभी इन-सर्विस उम्मीदवारों को प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाना चाहिए था यदि उन्होंने प्रवेश और पात्रता के लिए मानदंड पूरा किया। सभी मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने पूरी तरह जानते हुए अध्ययन अवकाश प्राप्त करने के लिए आवेदन किए कि इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए तीन वर्षीय नर्सिंग प्रशिक्षण को ड्यूटेशन पर नहीं माना जा सकता। सभी मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रशिक्षण पूरा किया या उनमें से कुछ इंटर्नशिप कर रहे थे या कुछ ने इंटर्नशिप पूरा करने के बाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के सामने रिट याचिका दाखिल की और प्रार्थना की कि उन्हें संबंधित प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई अध्ययन अवकाश को प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए। कि प्रार्ण एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित दिशानिर्देशों के साथ रिट याचिका संख्याओं को मंजूर किया:

उपरोक्त को देखते हुए, इन रिट याचिकाओं को निम्नलिखित दिशानिर्देशों के साथ निपटाया जा रहा है:

1. प्रतिवादियों को माननीय शीर्ष न्यायालय के निरीक्षणों और आशाओं का पालन करने के लिए कहा जाता है, जो कि सुशील शर्मा (उपरोक्त) [राजस्थान राज्य बनाम सुशील शर्मा, सिविल अपील नं. 5283/2001, दिनांक 10.08.2001] मामले में दिए गए हैं, इस प्रकार, वे किसी को भी नियम 112 के साथ साथ नियम 97 के उल्लंघन में ड्यूटेशन भत्ता का लाभ नहीं देंगे आर एस आर के। यह प्रतिवादी विभाग में पद की श्रेणियाँ के बावजूद है;

2. यदि कनिष्ठ विशेषज्ञ की कमी है, तो प्रयास किया जाना चाहिए कि नियमों में संशोधन किया जाए ताकि सीधी भर्ती की जा सके, क्योंकि वर्तमान में उक्त पद को केवल प्रमोशन द्वारा भरा जाता है। हालांकि, कनिष्ठ विशेषज्ञ की कमी के बहाने पर, प्रतिवादियों को नियमों को उल्लंघन या परिघातित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब यह सुशील शर्मा (उपरोक्त) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय की टिप्पणियों और आशाओं के खिलाफ भी जाता है। प्रतिवादियों को इस प्रकार नियम 111 और 112 के साथ साथ नियम 97 के अनुसार अध्ययन अवकाश और उस पर लाभ देने की अनुमति दी जाएगी।

3. चूंकि कई पदों के लिए, पूर्ण वेतन के साथ अध्ययन अवकाश का लाभ दिया गया है, इसलिए भेदभाव से बचने के लिए, प्रतिवादियों ने प्रार्थनाकर्ताओं को भी समान लाभ देने का सहमत किया है, हालांकि उक्त व्यवस्था केवल उनके लिए सीमित होगी जो पहले ही जीएनएम के प्रशिक्षण में शामिल हो चुके हैं और अब से आगे किसी को भी आरएसआरकी प्रावधानों का उल्लंघन करके अध्ययन अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा।

4. उक्त आदेश का पालन इसकी प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर किया जा सकता है।"

2.2 उसके बाद राज्य ने विभागीय पीठ के सामने अंतर-न्यायालय अपील की। विभागीय पीठ ने राज्य को रिव्यू आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी। राज्य ने सीखा हुआ एकल न्यायाधीश के सामने रिव्यू आवेदन दाखिल किए, जिन्हें खारिज कर दिया गया। बाद में, राज्य ने एक बार फिर एकल न्यायाधीश द्वारा पास की गई निर्णय(ओं) और आदेश(ओं) के खिलाफ प्रभागीय पीठके सामने अंतर-न्यायालय अपील की, जिसमें वृत्ति याचिकाएं स्वीकार की गई थीं और यह कहते हुए कि मौलिक वृत्ति याचिकाकर्ता अपने प्रशिक्षण की अवधि को उसके लिए स्वीकृत अवकाश की अवधि के रूप में देखने का हकदार हैं। इस आपत्तिग्रस्त सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय का विभागीय पीठ अंतर-न्यायालय अपील को स्वीकार करते हुए, एकल न्यायाधीश के पहले के निर्णय की स्वीकृति करते हुए यह निर्णय लिया कि इन-सर्विस उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि को ड्यूटेशन पर अवधि के रूप में नहीं देखा जाएगा और केवल उम्मीदवार के लिए स्वीकृत अवकाश के रूप में ही देखा जाएगा। इस अंतर-न्यायालय अपील के पेंडेंसी के दौरान, एकल न्यायाधीश द्वारा पास किए गए निर्णय और आदेश की अवहेलना की धमकी के तहत, मौलिक वृत्ति याचिकाकर्ता को राशि अदा की गई थी और उन्हें यह बताया गया था कि प्रशिक्षण की अवधि को उनके लिए स्वीकृत अवकाश की अवधि के रूप में ही देखा जाएगा। प्रभागीय पीठने भी निर्देशित किया कि राज्य को उम्मीदवारों को उनके प्रशिक्षण की अवधि के दौरान स्वीकृत अवकाश की अवधि के रूप में अधिक राशि वसूलने की स्वतंत्रता होगी, सरल समान किस्तों में।

2.3. विभागीय पीठ के उच्च न्यायालय द्वारा पास किए गए आपत्तिग्रस्त सामान्य निर्णय और आदेश से असंतुष्ट और आहत महसूस करते हुए, मौलिक वृत्ति याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की हैं।

3. पहले ही, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि इस न्यायालय ने वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं/अपीलों में सीमित पक्ष पर नोटिस जारी किया था, मौलिक वृत्ति याचिकाकर्ताओं से राशियों की वसूली के प्रति, जैसा कि आपत्तिग्रस्त निर्णय में निर्देशित किया गया था, और बीच में वसूली की स्थगन निर्देशित की गई थी। इस मामले के उस दृष्टिकोण में, अब विचार करने की आवश्यकता है, क्या मौलिक वृत्ति याचिकाकर्ताओं से राशियाँ वसूली जाएंगी, जैसा कि उच्च न्यायालय के प्रभागीय पीठद्वारा पास किए गए आपत्तिग्रस्त निर्णय और आदेश में निर्देशित किया गया है।

4. श्री आर.के. सिंह, मौलिक वृत्ति याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील, ने इस न्यायालय के निर्णय पर भारी भरकम निर्भर किया है, जो कि *पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह*, में रिपोर्टेड है (2015) 4 एस सी सी 334। उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रचंड रूप से साक्षात्कार किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय ने देखा और ठहराया है, क्लास III और क्लास IV सर्विस (ग्रुप C और ग्रुप D सर्विस) के कर्मचारियों से वसूली अनुमत नहीं है।

4.1 मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित प्रार्ण वकील ने प्रार्थना और प्रस्तावित किया है कि क्योंकि प्रत्येक मौलिक रिट याचिकाकर्ता कक्षा III और कक्षा IV की पोस्ट पर सेवानिवृत्त हैं, राज्य द्वारा पहले ही अधिक राशि को वापस नहीं किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप में, यह प्रार्थना की गई है कि मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं को उन्हें अधिक भुगतान की गई राशि को वापस करने के लिए योग्य मासिक किस्तें दी जाएंगी।

5. डॉ. मनीष सिंघवी, राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तावित किया है कि इस अदालत का *रफीक मसीह*, (उपरोक्त) के मामले में निर्णय, जिस पर मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने भरोसा किया है, हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है। इसे प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में राज्य/राज्य प्राधिकृत ने कर्मचारियों को गलती से राशि भुगतान की थी जिसे वापस किया जाना चाहिए था और उस परिस्थिति में इस अदालत ने निरीक्षण किया और ठहराया कि कक्षा III और कक्षा IV सेवा (समूह C और समूह D सेवा) के कर्मचारियों के मामले में अधिक भुगतान की गई राशि का पुनर्वास करना अनुमानित है। इसे प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में, यह मामला नहीं है जहाँ राज्य या राज्य प्राधिकृत ने गलती से अधिक राशि भुगतान की थी। बल्कि अधिक राशि का भुगतान उस आदेश के अनुसार किया गया था जो कि प्रार्ण एकल न्यायाधीश ने पास किया था, अवमानना प्रक्रिया की धमकी के तहत, जिसे अब प्रभागीय पीठने निरस्त कर दिया है। प्रस्तुत किया गया है कि एक बार जब प्रार्ण एकल न्यायाधीश द्वारा पास किया गया आदेश, जिसके अनुसार मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं को राशि दी गई थी, प्रभागीय पीठ द्वारा निरस्त कर

दिया गया, तो आवश्यक परिणाम उत्पन्न होंगे और पुनर्वापसी के सिद्धांत पर, राज्य को अधिक भुगतान की गई राशि वापस करने का अधिकार होगा।

5.1 इस अदालत के *इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल,* (पैराग्राफ़ 334 से 336), (2020) 8 एस सी सी 129 और इस अदालत *दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश,* (2003) 8 एस सी सी 648 (पैराग्राफ़ 25 से 30) मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है, पुनर्वापसी के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए।

5.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर, विशेषकर इस अदालत के पुनर्वापसी के सिद्धांत पर दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हुए, राज्य की ओर से उत्कृष्ट वकील ने प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, उच्च अदालत की प्रभागीय पीठने राज्य को अधिक भुगतान की गई राशि वापस करने की अनुमति देने में कोई त्रुटि नहीं की है। हालांकि, उत्कृष्ट वकील ने इमानदारी से कहा है कि मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं को उचित किस्तें दी जा सकती हैं, जिसे प्रभागीय पीठने आलोचित निर्णय में भी देखा है।

6.हमने प्रत्येक पक्ष के वकीलों से विस्तार से सुना है।

पहले ही, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मौजूदा मामले में अपीलांतों को अधिक राशि राज्य/राज्य प्राधिकृत अधिकारियों की किसी गलती के कारण नहीं दी गई थी। अधिक राशि विद्यमान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार भुगतान की गई थी, जिसे बाद में प्रभागीय पीठने रद्द कर दिया है। इसलिए, जब विद्यमान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित जजमेंट और आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसके तहत मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं को अधिक राशि दी गई थी, आवश्यक परिणाम उत्पन्न होने चाहिए। इसलिए, यदि राज्य ने राशि को गलती से नहीं भुगतान किया हो बल्कि इसे विद्यमान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार भुगतान किया गया हो जिसे बाद में रद्द कर दिया गया है, तो इस अदालत का *रफीक मसीह,* (उपरोक्त)) मामले में निर्णय लागू नहीं होगा। यह कहा गया निर्णय केवल उस केस में ही लागू हो सकता है जहाँ राज्य/राज्य प्राधिकृत अधिकारियों ने गलती से राशि भुगतान की हो और पाया जाता है कि कर्मचारी की तरफ से कोई दोष और/या कोई भ्रमित करने वाली बात नहीं है और कि संबंधित कर्मचारी को ऐसी अधिक राशि के लिए जिम्मेदार नहीं पाया गया है जो गलती से भुगतान की गई थी। एकल जज द्वारा पास किए गए आदेश के अनुसार अधिक राशि जो चुकाई गई है, जिसे प्रभागीय पीठने खारिज कर दिया है, उसे मूल रिट याचिकाकर्ता को वापिस करना होगा और/या वापिस देना होगा, जिसे राज्य को उनसे पुनर्वापसी के सिद्धांत पर वसूलने का अधिकार है।

6.1 इस स्थिति में, पुनर्वापसी के सिद्धांत पर इस अदालत का *इंदौर विकास प्राधिकरण* (उपरोक्त) मामले में दिया गया निर्णय संदर्भित किया जाना आवश्यक है। उस निर्णय में, इस अदालत की एक संविधान पीठ ने *दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड* (उपरोक्त) मामले में पहले किए गए निर्णय और पुनर्वापसी के सिद्धांत पर अन्य निर्णयों को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ 335 से 336 तक निम्नलिखित रूप में टिप्पणी और निर्णय दिया है:

पुनर्वापसी के सिद्धांत में :

"**335**. पुनर्वापसी का सिद्धांत मुद्दे की अंतिम निर्णय के बाद पूर्ण न्याय करने के आदर्श पर स्थापित है, और पक्षों को उसी स्थिति में रखा जाना चाहिए जैसे कि मुकदमेबाजी और मामले में कोई अंतरिम आदेश, अगर कोई है, न होता। *दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश*, [(2003) 8 एस सी सी 648] में कहा गया था कि कोई भी पक्ष मुकदमेबाजी का लाभ नहीं उठा सकता। अगर वह मुकदमा हार जाता है तो उसे देरी के कारण प्राप्त लाभ को उगलना होगा। अदालत द्वारा पास किया गया अंतरिम आदेश एक अंतिम निर्णय में विलीन हो जाता है। अंतरिम चरण में सफल पक्ष के पक्ष में पास किया गया एक अंतरिम आदेश की वैधता, अंतिम आदेश जो उस पक्ष के खिलाफ जाता है, उसे उलट दिया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 पुनर्वापसी का मूल स्रोत नहीं है। यह बल्कि न्याय, न्याय और इंसाफी के नियम की सांविदानिक मान्यता है . अदालत के पास पूर्ण न्याय करने के लिए पुनर्वापसी का आदेश देने का स्वाभाविक अधिकार है। यह सिद्धांत भी है कि एक गलत आदेश को जिन्दा रखकर और उसका सम्मान करकर उसे स्थायी नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालतें धारा 144 CPC के शर्तों के भीतर न आने वाली कई परिस्थितियों में पुनर्वापसी का सिद्धांत लागू कर चुकी हैं। पुनर्वापसी की प्राप्यता को आकर्षित करने वाली बात यह नहीं है कि अदालत का कृत्य गलत है या अदालत द्वारा कोई गलती या त्रुटि की गई है; परीक्षण है कि, किसी पक्ष की कृति के कारण अदालत को एक आदेश पास करने के लिए प्रेरित करने पर, जिसे अंत में स्थायी नहीं माना गया, जिससे एक पक्ष को वह लाभ प्राप्त होता है जो इसके अन्यथा नहीं मिलता, या दूसरे पक्ष को हानि उठानी पड़ती है, पुनर्वापसी की जरूरत होती है। मुकदमेबाजी को उत्पादक उद्योग बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुकदमेबाजी को गेमिंग में घटित नहीं किया जा सकता जहाँ प्रत्येक मामले में एक तत्व का मौका होता है। यदि पुनर्वापसी की धारणा को अंतरिम आदेशों के लागू होने से बाहर कर दिया जाए, तो मुकदमेबाज प्रतियोगी अंतरिम आदेश से उत्पन्न लाभ को निगलने का लाभ उठाएगा। इस अदालत ने *दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड* [(2003) 8 एस सी सी 648] में इस प्रकार कहा है: (एस सी सी pp. 662-64, **पैरा** 26-28)

"26. हमारी राय में, पुनर्वापसी का सिद्धांत इस सुझाव का ख्याल रखता है। शब्द "पुनर्वापसी" अपने एटिमोलॉजिकल संस का अर्थ है, किसी विशेष पक्ष को, एक निर्णय या आदेश की संशोधन, परिवर्तन या उलटाव पर, वापस करना जो उसे निर्णय या अदालत के आदेश का क्रियान्वयन करने में खो दिया गया है या सीधे तौर पर एक निर्णय या आदेश का परिणाम (*देखें ज़फर ख़ान बनाम बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू, यू.पी. [ज़फर ख़ान बनाम बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू, यू.पी.*, [1984 Supp एस सी सी 505]). कानून में, शब्द "पुनर्वापसी" तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है: (i) किसी के सच्चे मालिक या स्थिति को कुछ विशिष्ट चीज वापस करना या पुनर्स्थापन; (ii) दूसरे के लिए किए गए गलत काम से प्राप्त लाभ के लिए मुआवजा; और (iii) दूसरे को होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा या परिहार। (*देखें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी,* 7वां संस्करण, पृ. 1315। जॉन डी. कलामारी और जोसेफ़ एम. पेरिल्लो द्वारा *कॉंट्रैक्ट्स का लॉ, ब्लैक*। के द्वारा उद्धृत किया गया है कहने के लिए कि "पुनर्वापसी" एक अस्पष्ट शब्द है, कभी-कभी कुछ को उलटा देने को संदर्भित करता है और कभी-कभी किए गए चोट के लिए मुआवजा देने को संदर्भित करता है

अक्सर, शब्द के दोनों अर्थों के अंतर्गत परिणाम समान होता है। ... अन्यायपूर्ण कंगाली, साथ ही अन्यायपूर्ण समृद्धि भी, पुनर्वापसी का एक कारण है। यदि प्रतिवादी गैर-टॉर्टीयस मिस्प्रेजेंटेशन का दोषी है, तो वसूली का माप कठोर नहीं है परंतु, पुनर्वापसी के अन्य मामलों की तरह, ऐसे कारक जैसे कि आपसी दोष, सहमत जोखिम, और ना तो किसी भी पक्ष के दोष से संबंधित और ना ही सहमत अल्टरनेटिव जोखिम आवंटन की न्यायपूर्णता को तौलना करनी चाहिए।'

पुनर्वापसी का सिद्धांत संहिता सिविल प्रक्रिया, 1908 की धारा 144 में वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। धारा 144 सीपीसी न केवल एक निर्णय को परिवर्तित, उलटा, अलग किया जाने या संशोधित करने की बात कहती है, बल्कि एक आदेश को भी एक निर्णय के साथ समर्थान करती है। प्रावधान का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसमें एक निर्णय या आदेश के लगभग सभी प्रकार के परिवर्तन, उलटाव, पृथक्करण या संशोधन शामिल हैं। अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक अंतिम निर्णय में मिल जाता है। एक पक्ष के पक्ष में पारित एक अंतरिम आदेश की वैधता, अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप उस पक्ष के खिलाफ जाती है, जो अंतरिम चरण में सफल रहा है।

27. … यह भी उस सिद्धांत पर है कि एक गलत आदेश को जीवित रखकर और उसका सम्मान करके उसे बनाए रखना नहीं चाहिए (देखें *ए. अरुणगिरि नादर बनाम. एस.पी. रथिनासामी [ए. अरुणगिरि नादर बनाम. एस.पी. रथिनासामी* 1970 एस सी सी OnLine Mad 63])। ऐसी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालयों ने धारा 144 के शर्तों के अनुसार सख्त न आने वाली अनेक स्थितियों में पुनर्वापसी के सिद्धांत को लागू किया है।

28. कोई भी व्यक्ति अदालत के किसी कार्रवाई से परेशानी में नहीं होना चाहिए, यह नियम केवल अदालत की गलत क्रियावली से सीमित नहीं है; अदालत की "क्रियावली" उन सभी क्रियावलियों को अपने में शामिल करती है जिस पर अदालत किसी कानूनी प्रक्रिया में राय बना सकती है कि यदि उसे तथ्यों और कानून का सही ज्ञान होता तो वह ऐसा नहीं करती। … *पुनर्वापसीकी अवधारणा को अंतरिम आदेशों के लागू होने से बाहर कर दिया जाता है, तो वादी अंतरिम आदेश से उत्पन्न होने वाले लाभ को ग्रहण कर लेगा फिर भी* अंत में युद्ध हार जाता है। इसे मान्य नहीं किया जा सकता है। हम इस राय में हैं कि वह सफल पक्ष, जो अंत में मुद्दा जीतकर मौद्रिक रूप में राहत का हकदार होता है, उसे उस समय के लिए उचित ब्याज दर पर मुआवजा मिलना चाहिए जब तक अदालत का अंतरिम आदेश पैसे को जारी करने में स्थगित रहा होता है।"

(बल दिया गया है)

336. गुजरात राज्य बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड [गुजरात राज्य बनाम एस्सार ऑयल लिमिटेड, (2012) 3 एस सी सी 522 : (2012) 2 एस सी सी (Civ) 182] में, यह देखा गया था कि पुनर्वापसीका सिद्धांत अन्यायिक लाभ या अन्यायिक संपत्ति के खिलाफ एक उपाय है। अदालत ने नोट किया: (एस सी सी p. 542, पैरा 61-62)

"61. पुनर्वापसी की अवधारणा वास्तव में एक कॉमन लॉ प्रिंसिपल है, और यह अन्यायिक संपत्ति या अन्यायिक लाभ के खिलाफ एक उपाय है। इस अवधारणा की कोर में अदालत की अंतरात्मा होती है, जो एक पक्ष को किसी दूसरे से मिली कोई धनराशि या कुछ लाभ रखने से रोकती है, जिसे उसने अदालत के एक गलत फैसले के जरिए प्राप्त किया

है। ऐसा उपाय इंग्लिश लॉ में आमतौर पर एक कंट्रैक्ट या टॉर्ट में उपाय से अलग होता है और कॉमन लॉ उपाय की तीसरी श्रेणी में आता है, जिसे क्वासी-कंट्रैक्ट या पुनर्वापसीकहा जाता है।

62. अगर हम पुनर्वापसी की अवधारणा का विश्लेषण करें, तो एक बात स्पष्ट रूप से उजागर होती है कि रिस्टीट्यूट करने का कर्तव्य उस व्यक्ति या प्राधिकरण पर है जिसने अन्यायिक संपत्ति या अन्यायिक लाभ प्राप्त किया है (देखें Halsbury's Laws of England, 4th Edn., Vol. 9, p. 434)."

उक्त निर्णय में, यह आगे भी नोट किया गया है और माना गया है कि पुनर्वापसी प्रिंसिपल उस विचार को मानता है और उसे आकार देता है कि अदालत के आदेश के कारण, एक मुद्दती के प्रयास पर, प्राप्त लाभों को स्थायी नहीं बनाया जाना चाहिए।

6.2 *औसेफ मथई बनाम एम. अब्दुल खादिर के मामले में, जिसे (2002) 1 एस सी सी 319* में रिपोर्ट किया गया है, इसे नोट किया गया है और माना गया है कि लिस को खारिज करने के बाद, संबंधित पक्ष को उस स्थिति में वापस भेज दिया जाता है जो पेटीशन दायर करने से पहले मौजूद थी, उस अदालत में जिसने स्थगन प्रदान की थी।

6.3 वैसे भी, किसी को भी उस गलत आदेश का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसे अदालत ने पास किया था जिसे उच्च फोरम/अदालत ने बाद में सेट एसाइड कर दिया है। कानून की स्थापित स्थिति के अनुसार, कोई भी पक्ष अदालत के आदेश के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए।

7. वैसे भी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 पुनर्वापसी के लिए प्रावधान करती है। CPC की धारा 144 निम्नलिखित रूप में है:

"144. पुनर्वापसी के लिए आवेदन - (1) जहाँ और जितना एक डिक्री या एक आदेश किसी अपील, पुनरावलोकन या अन्य प्रक्रिया में बदल दिया गया है या उलट दिया गया है या किसी उद्देश्य के लिए स्थापित किसी मुकदमे में सेट एसाइड या संशोधित किया गया है, जिसने डिक्री या आदेश पास किया था, उसे किसी भी पक्ष के आवेदन पर, जो पुनर्वापसीया अन्यथा किसी लाभ के लिए अधिकारित है, ऐसा पुनर्वापसीकराना चाहिए जो, जितना संभव हो, प्रतिपक्षों को उस स्थिति में स्थानित करेगा जो वे किसी ऐसी डिक्री या आदेश के लिए धारण करते थे या उसका कोई हिस्सा जिसे बदल दिया गया है, उलट दिया गया है, सेट एसाइड या संशोधित किया गया है; और, इस उद्देश्य के लिए, अदालत किसी भी आदेश, लागत के वापसी और

ब्याज, मुआवजा, क्षतिपूर्ति और मेस्न प्रॉफिट्स के भुगतान के लिए आदेश कर सकती है, जो डिक्री या आदेश के ऐसे परिवर्तन, पलटाव, सेटिंग एसाइड या संशोधन पर संपत्ति से निकलते हैं।

व्याख्या - उप-खंड (1) के उद्देश्यों के लिए, "जिसने डिक्री या आदेश पास की थी, उस अदालत को माना जाएगा कि उसमें शामिल है,

(a) जहाँ डिक्री या आदेश को अपीलाते या पुनरावलोकन अधिकार का प्रयोग करके बदल दिया गया है, पहली अदालत;
(b) जहाँ डिक्री या आदेश को एक अलग मुकदमे द्वारा सेट एसाइड कर दिया गया है, ऐसी डिक्री या आदेश पास करने वाली पहली अदालत;
(c) जहाँ पहली अदालत मौजूद नहीं है या उसे इसे कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं है, वह अदालत जो, अगर डिक्री या आदेश पास किए जाने वाले मुकदमे को इस खंड के तहत पुनर्वापसीके लिए आवेदन करने के समय संस्थापित किया जाता, ऐसे मुकदमे का परीक्षण करने का अधिकार होता।

2. किसी भी पुनर्वापसीया अन्य राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा जो उप-खंड (1) के तहत आवेदन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।"

8. वर्तमान मामले में, एकल न्यायाधीष द्वारा पास किए गए आदेश को उच्च न्यायालय की विभागीय पीठ ने रद्द कर दिया है और इसलिए धारा 144 सीपीसी को भी लागू करते हुए, सीखे हुए एकल न्यायाधीष द्वारा पास किए गए आदेश के अनुसार चुकाए गए राशि को विभागीय पीठ द्वारा वापिस किए जाने का आवश्यकता है, उसे मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस करना होगा।

इस प्रकार, मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, जो यहाँ उपर वर्णित हैं, उच्च न्यायालय की विभागीय पीठ को राज्य के पक्ष में अधिक चुकाई गई राशि वसूलने के लिए स्वतंत्रता आरक्षित करना पूर्णतः उचित है। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अधिक चुकाई गई राशि को आसान समान किस्तों में वसूला जाना चाहिए, इसे लेकर विभागीय पीठ ने ऐसा निरीक्षण किया है, जबकि वसूलने के लिए स्वतंत्रता आरक्षित की गई है।

9. उपरोक्त और उपर्युक्त कारणों के लिए, उच्च न्यायालय की विभागीय पीठ ने राज्य के पक्ष में अधिक चुकाई गई राशि को मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं से वसूलने के लिए स्वतंत्रता आरक्षित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। हालाँकि, एक ही समय में, मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए, राशि को आसान समान किस्तों में वसूलने के लिए, हम निर्देशित करते हैं कि जो राशि मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं को अधिक चुकाई गई है, उसे एकल न्यायाधीष द्वारा पास किए गए आदेश के अनुसार, मौलिक रिट याचिकाकर्ताओं से तीस बराबर मासिक किस्तों में वसूला जाए, जो उनकी सैलरी से अप्रैल, 2022 से कटेगी।

10. इस प्रकार, तात्कालिक अपीलें उपर्युक्त शर्तों में निपटाई जाती हैं। कोई लागत नहीं।

निधि जैन अपीलें निस्तारित की जाती हैं।
(सहयोग द्वारा: नेहा शर्मा, एलसीआरए)

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित